

संपादक की कलम से

सावधान? मानवीय जीवन परमाणु युद्ध के कगार पर

आज पूरा वैश्विक परिवृश्य और पृथ्वी परमाणु युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठी हुई है। परमाणु संपन्न देशों के तमाम शासक और हुक्मरान अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं, मंसूबे और सनक को पूरा करने के लिए एक दूसरे के रक्त के घासे बन हुए हैं। परमाणु संपन्न देशों में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया ऐसे देश हैं जिनकी बागडोर सनकी तानाशाही प्रशासकों के हाथों में हैं और ये देश अपनी विस्तार वादी महत्वाकांक्षा और सनक के चलते परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगेल इतिहास गवाह है की सनकी प्रशासकों से हमेशा मानवता और शांति को युद्ध और हिंसा का खतरा बना रहता आया है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी तथा हिरोशिमा में युद्ध की सनक में परमाणु बम से हमला कर लाखों लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया था। इसके अलावा परमाणु हथियारों के उपयोग से पैदा हुए विकरण से आज भी जापान में बच्चों पर अप्राकृतिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इधर हम यदिं उत्तर कोरिया के सनकी शासक किम योंग की बात करें तो वर्ष 2022 की शुरूआत के बाद से उत्तर कोरिया ने 100 से अधिक हथियारों के परीक्षण किए हैं विशेष तौर पर कुछ अमेरिकी मुख्य भूमि और उनके खास सामरिक सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान पर हमला करने के लिए डिजाइन की हुई परमाणु मिसाइल भी शामिल हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका को लक्ष्य बनाकर क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण भी करता आ रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारी तबाही का मंजर तो सामने आ ही गया है। इसके अलावा यूक्रेन की अमेरिकी तथा नाटो देशों की मदद से नाराज होकर रूस स्पष्ट तौर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सार्वजनिक धमकी कई बार दे चुका है, उल्लेखनीय है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को जितना जान माल का नुकसान हुआ है उसके बाबर भी रूस में सामरिक हथियारों और सैनिकों की जान गई है। रूस को इसके बात का जरा भी अंदाजा नहीं था की यूक्रेन इतने दिन तक युद्ध को खींच सकता है। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी अपनी सनक के चलते परमाणु बमों से हमला भी कर सकता है। चीन और ताइवान विवाद में भी चीन के तानाशाही सीमा जिनपिंग अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और अमेरिका के परोक्ष रूप से ताइवान की मदद के कारण नाराजगी के चलते ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। स्पष्ट है कि रूस चीन और उत्तर कोरिया तीनों परमाणु संपन्न देश अमेरिका के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन नई परास्थितियों में बन चुके हैं। और यह भी खुला और सब विदित तथ्य है अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की जनना तथा राजनीतिक पार्टियों के दबाव में विश्व का सुरीमो बने रहने के चलते युद्ध में यांत्रियों के चलते अमेरिका को चीन रूस और उत्तर कोरिया फूटी आंखों नहीं अच्छे लगते हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया की सेना अपने वार्षिक सैन्य अभ्यास की ओर अग्रसर होकर लगातार समुद्र तथा उत्तर कोरिया की सीमा पर चक्कर लगा रही है। उत्तर कोरिया इसे अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया के हमले के पूर्वाभ्यास की तरह आंकलन कर रहा है। उधर अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया अपने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु एवं मिसाइलों का मुकाबला करने हेतु संयुक्त रूप से बैलैस्टिक मिसाइल निर्माण तथा प्रयोग के सहयोग के लिए सहमति दे चुके हैं।

इन तानों दर्शकों का सयुक्त तयारी का दखत हुए उत्तर कारिया के नेता किम जोंग ने रणनीतिक क्रूज मिसाइल के प्रावेगिक परीक्षण का निरीक्षण भी किया है।

अमेरिका तथा पश्चिमी देश हर उस देश का साथ देने को तैयार है जो

जमराका तथा पाश्चात्यम् दरा हर उस दरा का साथ दन का तैयार ह जो मूल रूप से चीन, उत्तर कोरिया और रूस का विरोध करते हैं। अमेरिका में चूंकि वर्ष 24 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं ऐसे में वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडन को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए एक बहुत बड़े मुद्दे की तलाश जरूर होगी और इसके चलते वह अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए किसी भी देश से अपनी बादशाहत बचाने के लिए युद्ध कर सकते हैं। और यह जाहिर है कि उनके किसी भी युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अस्ट्रेलिया, इंजरायल आंख मूंदकर साथ देने को तैयार होंगे। इधर भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही चीन से परंपरागत दुश्मनी चली आ रही है दूसरी तरफ भारत रूस का अभिन्न मित्र भी है भारत परंपरागत रूप से रूस का समर्थन करते आया है या अलग बात है कि अमेरिका से उसके संबंध पिछले 10 सालों से काफी मधुर हो गए हैं और वह सदैव शांति का पक्षधर रहा है।

कॉप 28 रहा कितना सफल

संयुक्त राष्ट्र के फ्रमवक कन्वेशन आन क्लाइमट चज (यूएनएफसीसीसी)का 28 वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप 28, सम्मेलन तेल और गैस उत्पादक देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई में आयोजित हुआ। यह सम्मेलन एक तनावपूर्ण परिवेश में संपन्न हुआ क्योंकि अपने देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी के मुख्य कार्यकार्थी अधिकारी सुल्तान अल जबर कॉप 28 के अध्यक्ष की हैसियत से इस सम्मेलन में एक दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में यूएई और अन्य सदस्य देशों के बीच हितों के टकराव की स्वाभाविक आशंका हर किसी को थी। दूसरी तरफ इसराइल और फिलिस्तीन वे बीच हिंसक झड़पों के कारण भी सम्मेलन के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे। बहरहाल विषमताओं के बावजूद लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने रेंगिस्तान में बंसे आलीशान दुर्बिल में आयोजित एक्सपो 2020 वेन्यू में शिरकत की। कइयों की नजर में यह सम्मेलन यह बताने का एक महत्वपूर्ण रूपक भी है कि किस प्रकार कौन सम्मेलनों ने यूएनएफसीसीसी के केंद्रीय मामलों के परे खुद का विस्तार ग्रीन वाशिंग के छलावे के तौर पर किया है।

एक नई विषय-सूची को सुगठित एंड डेमैज फंड के परिचालन के लिए राजकीय सम्मेलन में सभा प्रतिभागियों द्वारा सहमत के आधार पर पहल हा दिन नई अध्यक्षता ने सम्मेलन के पहले ही दिन अपनी राजनीतिक सूझ़ा-बूझा से विकसित देशों को लॉस एंड डैमैज फंड के परिचालन के लिए राजकीय करके सबको अर्चन्भित कर दिया और इसको क्रियान्वित करने के लिए अपनी ओर से अनुदान-आधारित प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस कार्यवाहानी ने हानि और क्षति के बीच अनुदान और समझौते के बाद के चरणों में उपस्थित होने वाली अन्य मार्गों के कारण प्रकट होने वाली लेन-देन की स्थितियों को भी सफलतापूर्वक दूर किया। इस सकारात्मकता वे साथ सम्मेलन की शुरूआत करना एक महत्वपूर्ण बात थी, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच एक विश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई। यह जरूरी इसलिए भी था क्योंकि इस कॉप के जिम्मे पेरिस समझौते के लक्ष्यों के ग्लोबल स्टॉकटेक आकलन के आधार पर सहमतिपूर्वक आगे ले जाने का दारोमदार भी था। इस बातचीत के समानांतर कई देशों ने स्वैच्छिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को तिगुना बढ़ाने की प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन और लोक स्वास्थ्य के प्रति संकल्प, टिकाऊ कृषि व अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें कई देशों ने समर्थन दिया तो कई चुप रहे। ऐसे देश चुप रहे जो स्वेच्छा या संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के नियमों या प्रोटोकॉल से बंधे हुए नहीं हैं। भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने भी पेरिस समझौते में अपने संकल्पों से परे इन बिंदुओं पर सहमत नहीं होने के लिए दिया है।

ईडी के खिलाफ खुली अराजकता का दुस्साहस कब तक?



मनोविल बढ़ा ह। इस ममता से एवं कार्यकर्ता सकार को पोकेट में मालते हुए न केवल की धज्जियां उड़ाते हैं बल्कि आजकल तो जैसे ही वह किसी मामले की जांच शुरू करती है, तुरंत ही अरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि यह काम राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। ऐसी संस्था कैसे निष्पक्ष दिखाई दे एवं कैसे स्वतंत्र होकर अपना काम करे? पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह उसका तरीका नहीं है, वह आपत्तिजनक और अपराधिक है। ममता की तानाशाही का ही परिणाम है कि उनके कार्यकर्ता बेखौफ हर चीज का फैसला अपने ढंग से करना-कराना चाहते और इसके लिये खुलेआम हिंसा एवं अराजकता का सहारा लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए यह नई बात नहीं है, चुनावी हिंसा एवं प्रतिहिंसा तो वहां लगातार चलती रहती है। अगर कोई व्यक्ति अंगुली उठाता है या विरोध करता है तो उसकी जान पर बन आती है। ममता खुद मुख्यमंत्री होकर अपने एक कार्यकर्ता छुड़ाने एक बार थाने पहुंच गयी थी, स्वाभाविक ही है कि वे अपने कार्यकर्ताओं का गलत एवं अलोकतात्रिक तरीके से समर्थन एवं सहयोग करती है जिससे उनका

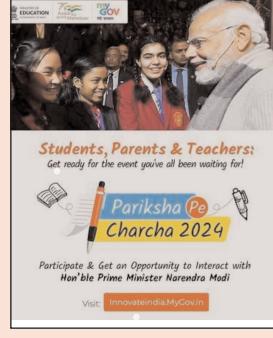
मथक
अपनी
कानून
बलिक
ओं का
बोटे बाटे
तीस
दिया
वैलिये
में बांट
र वहां
में भी
है, जो
क हो
जनीति
हों पर
जैसे
और
ता एवं
दिखते
हुआ
त्ति में
सी न
ओछी
हाथ में
नायक
प्रसिद्ध

शायर नज़ा न कहा ह कि अप
खिड़कियों के कांच न बदलो नज़ा
अभी लोगों ने अपने हाथ से पत्थर
नहीं फैके हैं। डर पत्थर से नहीं रुक
उस हाथ से है, जिसने पत्थर पकड़
रखा है। पश्चिम बंगाल में हर टीएम
कार्यकर्ता ने पत्थर पकड़ रखा
कानून एवं व्यवस्था नाम की कं
चीज वहां नहीं है। ईडी के अधिकारी
तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता के छा
छापेमारी करने गए थे, वह करो
रुपये के राशन घोटाले में गिरफ्तार
राज्य मंत्री ज्योतिर्प्रिय मलिक के
करीबी है। यदि ईडी अधिकारियों व
यह कथन सही है तो बेहद गंभीर
बात है।
पश्चिम बंगाल में आर्थिक अपराध
एवं घोटाले बड़े पैमाने पर हो रहे हैं
इन्हीं में से कुछ पर ईडी अंग
सीबीआई जांच कर रही है। इ^३
मामलों में तृणमूल कांग्रेस
विधायक और मंत्री भी आरोपित हैं
हालांकि इनमें से कई मामलों व
जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय
आदेश पर हो रही है, फिर भी ममता
सरकार का यही आरोप रहता है कि
केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके नेतृत्व
के खिलाफ राजनीतिक बदले व

भावना के तहत कारबाहि कर रहे हैं। यदि उसे वास्तव में ऐसा ही लगता है कि वे बेदाहा हैं, तो फिर घपले-घोटालों के गंभीर आरोपों से विरोध उसके नेताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, अपने पक्ष में सबूत और तर्क पेश करने चाहिए। इस तरह लाठी-डंडे के जोर पर वे कब तक हकीकत एवं सच्चाई पर पर्दा डालने में कामयाब हो सकते हैं। आये दिन ऐसे लोग, विषवमन करते हैं, प्रहार करते रहते हैं, चरित्र-हनन करते रहते हैं, सद्ग्रावना और शांति को भंग करते रहते हैं। उन्हें प्रांत में शांति, आदर्श-निष्पक्ष शासन-व्यवस्था, भाईचारे और एकता से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे धाव कर देते हैं जो हथियार भी नहीं करते। किसी भी टूट, गिरावट, दंगों व युद्धों तक की शुरूआत ऐसी ही बातों से होती है।

यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में इडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों पर निर्भर रहना पड़े। बंगाल में उन्हें ऐसा ही करना पड़ा। ऐसी ही स्थितियां अन्य गैर-भाजपा राज्यों में हैं। दिल्ली में (ललित गर्ग)
ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन,
पटपड़गांज, दिल्ली-92
फोन: 22727486,
9811051133

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों को तनाव से मुक्ति का सशक्त माहौल देता है



गान्धीया - वरशक स्तरपर दुनिया

के हर देश के छात्रों के लिए जो अनेक शिक्षा क्षेत्र में अध्यनरत हैं, अनेकों के लिए चिंता मुश्किल व सोचनीय स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब उनके जीवन पर असर डालने वाले बोर्ड की परीक्षाओं का पल सामने आता है। यह एक ऐसी घड़ी होती है कि अच्छे-अच्छे होशियार छात्र भी उम्मीद के विपरीत स्थिति महसूस करते हैं। या उनमें कि परीक्षा के

Students, Parents & Teachers!
Get ready for the event you've all been waiting for!

Pariksha Pe Charcha 2024

Participate & Get an Opportunity to interact with Hon'ble Prime Minister Narendra Modi

Visit [InnovateIndia.MyGov.in](#)

- जिसमें दशभर के साथ-साथ विदेशों से भी छात्र, अधिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बातचीत करते हैं। यह आयोजन शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पिछले छह वर्षों से सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावार माने के लिए सामाजिक समर्पण की जाएगी।

विवरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े अंदोलन -एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। यह एक ऐसा अंदोलन है जो प्रधानमंत्री के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के एक साथ लाने के प्रयासों से प्रेरित है ताकि एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया जा सके जहां प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व का उत्सव मनाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और आत्मभिंబ?वक्ति की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स इस पहल को प्रोटोटाइपिंग कर रही है। लगभग 2050 प्रतिभागियों का चयन मायगोव पोर्टल पर उनके प्रश्नों के आधार पर किया जाएगा। उन्हें एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट प्रदान की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में एग्जाम वॉरियर्स और एक प्रमाण पत्र शामिल होगा। 12 जनवरी (विवेकानंद के जन्मदिवस) 2024 यानी युवा दिवस से शुरू होकर 23 जनवरी (सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस) 2024 तक मुख्य कार्यक्रम के अग्रदृष्टि के रूप में, स्कूल स्तर पर विभिन्न न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जिनमें मैराथन दौड़, संगीत प्रतियोगिता जैसी अनंददायक सीखने की गतिविधियाँ शामिल होंगी। इनमें मीम प्रतियोगिता, नुकड़ नाटक, छात्र-एंकर-छात्र-अतिथि चर्चा आदि शामिल हैं। आखिरी दिन, 23 जनवरी 2024 यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की जयंती पर, देश भर के 500 जिलों में एक चिक्कला ननाइगा, जो आपके पास नवृत्त होगा। आज से 30-40 साल बाद जब सफलता को चूमेंगे और मैं अगर जीवित रहूंगा तो गर्व से कहूंगा कि यह बही लोग हैं जिनका मुझ जनवरी को दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। मैं गर्व करूंगा कि जब आपके हाथ में देश का नेतृत्व होगा। संतोष होगा कि इनसे मैंने बात की थी। परीक्षा जिंदगी नहीं है, परीक्षा जिंदगी में महज एक मुकाम है। आप में से बहुत से लोग हैं, जिन्हें शायद यहां भौका नहीं मिला। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। पीएम ने कहा था, जीवन में हर किसी को कुछ न कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। अगर आप किसी की देखादेखी में कोई काम करते हैं, तो बहुत निराशा हाथ लगेगी। अगर अपने मन का काम करेंगे, तो मजा आएगा। जिंदगी में अगर एकाध एंट्रीस में रह गए तो क्या। लाखों लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम डर के कारण कदम ही न रखें तो उससे बुरा कुछ नहीं। हमेशा अपने अंदर के विद्यार्थी को जीवित रखें। जीवन जीने का यही मार्ग है, नया-नया जानना।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों को तनाव से मुक्ति का सशक्त माहौल देता है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 29 जनवरी 2024 के एतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की संभावना-पंजीकरण की 12 जनवरी 2024 अंतिम तारीख दिशेभर के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों में परीक्षा पे चर्चा के प्रति व्यापक उत्साहजनक है। क्या ऐसे देश खेलों में आगे बढ़ेगा? देश को मेडल दिलाने वाले इंसाफ की मुद्रार लगा रहे हैं।

पहलवान कुश्ती महासंघ से दो-दो हाथ करने तुरे हैं। अधिकारी इस खेल और सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? किसकी सरकार है या किसकी थी, ये मुझ नहीं है। सवाल ये है कि क्या महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण होता है? या फिर ये सियासती मामला है। मुझ महिला खिलाड़ियों की सम्मान एवं मानसिक, शारीरिक सुरक्षा का है। अगर कुश्ती में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो महिला खिलाड़ियों में हर खेल के प्रति रुक्खान खत्म हो जायेगा। उनका मनोबल गिर जायेगा। महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम हो जायेगी। देश की प्रतिष्ठा और महिला खिलाड़ियों की अस्मिता का सवाल है। क्या राजनीति के बलरे दम तोड़ जाती है प्रतिभाएं? खेलों में राजनीति के सक्रिय होने से प्रतिभावान खिलाड़ियों को दबाया जाता है। खिलाड़ी हमेशा खेल अधिकारियों के दबाव में रहते हैं। खेलों में महनत करने वालों की प्रतिभाएं दबकर रह जाती हैं और आवाज उठाने पर खत्म कर दिया जाता है। इसका दुष्परिणाम यह है कि आज अभिभावक कुश्ती या अन्य खेल में अपनी बेटी का भेजते कई बार सोचेंगे। देश में अभिभावक पहले ही अपनी बेटी की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चिंतित रहते हैं, इस प्रकरण ने उनकी चिंता और बढ़ायी है। अब वे बेटी को खेल विशेषकर कुश्ती में भेजते हुजार बार सोचेंगे। हाल ही में सरकार ने नए चुनाव का भले ही रद्द कर दिया हो किंतु लंबे समय से कुश्ती संघ में दबदबा कायम रखें राजनीतिज्ञ चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध कोर्ट जाएंगे। इनका प्रयास होगा कि कुश्ती संघ की सियासत उनके हाथ से न जा पाए। भले ही सरकार ने नए चुनाव को रद्द करके यह संदेश देने का प्रयास किया है कि कुश्ती संघ को नियमों का पालन करना होगा। लेकिन खेल संघ से राजनीतिक लोगों को दूर रखने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। खिलाड़ी भी यदि राजनीति में आ जाए तो उसे भी खेल संघ से बाहर ही रखा जाना चाहिए। सुनील कार्ट भी खेल संघों में राजनीतिक दबल को लेकर चिंता जता चुका है और इसे कटाई जायज नहीं ठहराता। खेलों में सियासत का सकारात्मक प्रभाव समाज में एकात्मकता और सामाजिक समर्थन की भावना लेकर आता है और खिलाड़ियों को एक सकारात्मक पहचान बनाए रखने में मदद करता है वही इस बात की अनदेखी भी की नहीं की जा सकती कि कई बार अमुक खिलाड़ी को मनजाहे स्थान पर पहुंचाने के लिए सियासी दबाव और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है।

सियासी हस्तक्षेप नेताओं की बीच जातिवाद धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक असंतुलन लाता है और खेलों को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में सियासी दलों ने कुश्ती को अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करने का दुष्प्रयास किया है जिससे खिलाड़ियों और खेल समर्थकों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। सियासत का प्रयोग खेल और खिलाड़ियों के विकास में किया जाना चाहिए। निजी लाभ और निजी प्रकरणों का समायोजन खेल भावना से दूर होना चाहिए। ताकि वह खेल देश को गौरवान्वित करें और करता रहे। खेलों को सियासी बनान वाले मध्ये

खला म राजनात खल और खिलाड़ी दोनों के लिए चिंताजनक

-डॉ। सत्यवान सौरभ कुश्ती को लेकर मध्य बवाल के बीच खिलाड़ी भी सियासी रंग में रंगे नजर आने लगे हैं। यह खेल और खिलाड़ी दोनों के भविष्य के लिए चिंताजनक है। खेलों में सियासत ठीक नहीं है। खेलों में पक्ष-विपक्ष की राजनीति खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए चिंताजनक है। खेलों में राजनीति गलत है। खेल साफ, स्वच्छ और पारदर्शी होने चाहिए वर्तमान कुश्ती संघ और सियासती विवाद से दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। पिछले लगभग एक साल के भारतीय कुश्ती को सियासत ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों के आरोप लाने के बाद से ही सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए था, किंतु सियासत के चलते ऐसा नहीं हुआ। यह खेलों पर एक बदनुमां दाग, शर्म का विषय और त्रासदी है। देश के जो खिलाड़ी विदेशी सरजर्मी पर तिरणे का मान बढ़ाते आए उन्हें अपने अधिकारों के लिए जंतर-मंतर पर धरना देना पड़ रहा

है। क्या ऐसे देश खेलों में आगे बढ़ेगा? देश को मेडल दिलाने वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पहलवान कुश्ती महासंघ से दो-दो हाथ करने उत्तरे हैं। आखिर इस खेल और सियासी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? किसकी सरकार है या किसकी थी, ये मुझ्हा नहीं है। सवाल ये है कि क्या महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण होता है? या फिर ये सियासती मामला है। मुझ्हा महिला खिलाड़ियों की सम्मान एवं मानसिक, शारीरिक सुरक्षा का है। अगर कुश्ती में बैटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो महिला खिलाड़ियों में हर खेल के प्रति रुक्षान खस्त हो जायेगा। उनका मनोबल गिर जायेगा। महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम हो जायेगी। देश की प्रतिष्ठा और महिला खिलाड़ियों की अस्मिता का सवाल है। क्या राजनीति के बलते दम तोड़ जाती है प्रतिभाएँ? खेलों में राजनीति के सफ्रिय होने से प्रतिभावान खिलाड़ियों को दबाया जाता है। खिलाड़ी हमेशा खेल अधिकारियों के दबाव में रहते हैं। खेलों में मेहनत करने वालों की प्रतिभाएँ दबकर रह जाती हैं और आवाज उठाने पर खत्म कर दिया जाता है। इसका दुपरिणाम यह है कि आज अभिभावक कुश्ती या अन्य खेल में अपनी बेटी का भेजते कई बार सोचेंगे। देश में अभिभावक पहले ही अपनी बेटी की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चित्ति रहते हैं, इस प्रकरण ने उनकी चिंता और बढ़ायी है। अब वे बेटी को खेल विशेषकर कुश्ती में भेजते हुए बार सोचेंगे। हाल ही में सरकार ने नए चुनाव का भले ही रद्द कर दिया हो किंतु लंबे समय से कुश्ती संघ में दबदबा कायम रखें राजनीतिज्ञ चुप बैठने वाले नहीं हैं। वे सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध कोट्टा जाएंगे। इनका प्रयास होगा कि कुश्ती संघ की सियासत उनके हाथ से न जा पाए। भले ही सरकार ने नए चुनाव को रद्द करके यह संदेश देने का प्रयास किया है कि कुश्ती संघ को नियमों का पालन करना होगा। लेकिन खेल संघ से राजनीतिक लोगों को दूर रखने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। खिलाड़ी भी यदि राजनीति में आ जाए तो उसे भी खेल संघ से बाहर ही रखा जाना चाहिए। सुप्रीम काट भी खेल संघों में राजनीतिक दखल को लेकर चिंता जता चुका है और इसे कटाई जायज नहीं ठहराता। खेलों में सियासत का सकारात्मक प्रभाव समाज में एकात्मकता और सामाजिक समर्थन की भावना लेकर आता है और खिलाड़ियों को एक सकारात्मक पहलवान बनाए रखने में मदद करता है वही इस बात की अनदेखी भी की नहीं की जा सकती कि कई बार अमुक खिलाड़ी को मनचाहे स्थान पर पहुंचाने के लिए सियासी दबाव और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है।

सियासी हस्तक्षेप नेताओं के बीच जातिवाद धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक असंतुलन लता है और खेलों को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में सियासी दलों ने कुश्ती को अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करने का दुष्प्रयास किया है जिससे खिलाड़ियों और खेल सर्वथों को काफी बड़ा नुकसान हआ है। सियासत का प्रयोग खेल और खिलाड़ियों के विकास में किया जाना चाहिए। निजी लाभ और निजी प्रकरणों का समायोजन खेल भावना से दूर होना चाहिए। ताकि वह खेल देश को गौरवान्वित करें और करता रहे। खेलों को सियासी बनाने वाल मद्दे

